

सुबह से शाम

S.S. Media
Group

तक की खबरें

मूल्य - 2₹

* वर्ष: 19 * अंक: 16 * मुंबई, रविवार, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर २०२६ * संपादक:- एस.के.तिवारी * पेज: 4

Email Id - ssnews2008@gmail.com

www.subahsesham.com

ममता बनर्जी की श्रीरामपुर रैली से पहले बवाल, कुणाल घोष की कार पर पथराव और अंडे फेंके

संवाददाता

श्रीरामपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले राजनीतिक तनाव के बीच शनिवार, 26 सितंबर को श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में ममता बनर्जी की जनसभा से पहले बड़ा बवाल हुआ। सभा में शामिल होने जा रहे तुणमूल विधायक कुणाल घोष की कार को उत्तरपाड़ा इलाके में भीड़ ने घेर लिया। सामने आए वॉडियों में उनकी कार पर अंडे और पत्थर फेंके जाते तथा पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। कुणाल घोष ने हमलावरों को भाजपा से जुड़ा बताया, जबकि भाजपा ने इस आरोप से इनकार किया। पुलिस ने तत्काल किसी संगठन की जिम्मेदारी तय नहीं की थी। घटना के बाद कुणाल घोष श्रीरामपुर की सभा तक नहीं पहुंच सके और वापस कोलकाता की ओर लौट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को रास्ते में रोककर हमला किया गया और उस समय

उत्तरपाड़ा में काले झंडों के बीच घिरी कार, शीशा टूटा; कुणाल घोष ने भाजपा पर लगाया हमले का आरोप, भाजपा ने किया इनकार



वहां पर्याप्त पुलिस मौजूद नहीं थी।

इसी बीच ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा था और उनकी पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को श्रीरामपुर की सभा में पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि बाद में ममता बनर्जी पुलिस सुरक्षा

के बीच श्रीरामपुर कोर्ट मैदान पहुंचीं। इसलिए उन्हें पूरे दिन 'नजरबंद' रखे जाने की बात को तथ्य के बजाय उनके आरोप के रूप में ही लिखा जाना उचित है। सभा को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी खींचतान चल रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26 (शेष पेज 2 पर)

भारत के पास 'तर्क की शक्ति' के साथ 'शक्ति का तर्क' भी: राजनाथ सिंह

संवाददाता

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए कूटनीति और सैन्य क्षमताओं के बीच संतुलन जरूरी होने पर जोर देते हुए कहा कि भारत के पास "तर्क की शक्ति" के साथ-साथ "शक्ति का तर्क" भी है और जरूरत पड़ने पर भारत उसी भाषा में जवाब देगा, जिसे दूसरा पक्ष समझता है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक रक्षा सम्मेलन (डिफेंस कॉन) को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि "सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर का नेतृत्व कर रहे कुछ नेताओं ने इन दोनों विचारों को साथ लेकर चलने के बजाय "शक्ति और नैतिकता को एक-दूसरे का विकल्प मान लिया।" उन्होंने दावा किया कि 1960 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद "स्वीकार



किया था कि हम वास्तविकता से कट गए थे और अपने ही बनाए एक काल्पनिक माहौल में जी रहे थे। रक्षा मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि बाद में देश का नेतृत्व करने वाले कई अन्य नेताओं ने इससे कोई सबक नहीं लिया और अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह था कि लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करने वाले कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि "जिस तरह भारत शांति के पक्ष में है, उसी तरह दूसरे देश भी शांति के पक्ष में हैं।" एक निजी चैनल द्वारा आयोजित 'डिफेंस कॉन' में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में इस सोच में "बड़ा बदलाव" आया है। उन्होंने कहा, "हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास तर्क की शक्ति भी है और शक्ति का तर्क भी। इसलिए जरूरत पड़ने पर हम उसी भाषा में जवाब देंगे, जिसे दूसरा पक्ष समझता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत कूटनीति के माध्यम से दुनियाभर में शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। साथ ही किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र और कूटनीति के माध्यम से समाधान का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ने पर ऐसा करता भी है। रक्षा मंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक और पिछले साल किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए "जरूरी क्षमताएं" भी हैं और उनका इस्तेमाल करने की "इच्छाशक्ति" भी है।

राज्य के 265 तहसीलों में सूखा घोषित: किसानों को राहत के लिए 12 उपाय लागू करेगी सरकार

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में बारिश की कमी के कारण पैदा हुई सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 265 तहसीलों को सूखा घोषित करते हुए तत्काल पंचनामा शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों, विद्यार्थियों, नागरिकों और पशुधन को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 12 उपाय और रियायतें लागू करने की घोषणा की है। शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "सूखे की स्थिति में राज्य के किसान, खेतिहर मजदूर और मेहनतकश लोग हमारी सहायता के केंद्र में हैं। उन्हें राहत देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। हम किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सभी एकजुट होकर प्रयास करें। इस संबंध में शासन निर्णय जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावित तहसीलों में तत्काल पंचनामा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग

और संबंधित सभी एजेंसियों को संवेदनशीलता तथा आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सर्वेक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। सर्वेक्षण के दौरान फसलों की वास्तविक स्थिति के फोटो और GPS कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे और इनके आधार पर फसल स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य के कृषि आयुक्त ने खरीफ-2026 मौसम की समीक्षा के बाद 265 तहसीलों में सूखे की स्थिति होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जून से अब तक बारिश की कमी और अन्य कारकों से प्रभावित इन तहसीलों में सूखा प्रबंधन संहिता-2016 के तहत Trigger-1 के अनुसार पंचनामा किया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों में भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋण की वसूली पर स्थगन, कृषि पंपों के चालू बिजली बिल में राहत, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करना, रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक काम शुरू करना, जरूरत के अनुसार पेयजल के लिए टैंकर उपलब्ध कराना, कमी घोषित गांवों में कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति न काटना, किसानों और

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल पंचनामा शुरू करने के लिए निर्देश, फसल ऋण पुनर्गठन, कर्ज वसूली स्थगन, परीक्षा शुल्क माफी और बिजली बिल में राहत



खेतिहर मजदूरों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, जलसंधारण के काम शुरू करना तथा पेयजल और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था शामिल है। सरकार के अनुसार 7.5 हॉस्पेयर तक क्षमता वाले कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों को घोषित राहत का लाभ दिया जाएगा।

छह राजस्व विभागों के 265

तहसील शामिल

‘ट्रिगर-1’ के तहत ठाणे राजस्व विभाग के 12, नासिक के 49, पुणे

के 35, छत्रपति संभाजीनगर के 74, अमरावती के 56 और नागपुर राजस्व विभाग के 39 तहसील शामिल किए गए हैं। ठाणे राजस्व विभाग में रायगढ़ जिले का श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिले के रत्नागिरी, संगमेश्वर और राजापुर तथा सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी, दोडामार्ग, कणकवली, कुंडाल, वैभववाड़ी, मालवण, देवगढ़ और वेगुली शामिल हैं। ठाणे और पालघर जिले की किसी भी तहसील को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार और अहिल्यानगर (शेष पेज 2 पर)

लिया गया है। विशेष सूचना के आधार पर DRI ने मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) की मदद से 23 सितंबर की सुबह दुबई से आए तीनों यात्रियों को रोका। उनके सामान की गहन जांच के दौरान करीब 33.50 किलोग्राम ऐसे खाद्य पदार्थ मिले, जिनमें सोने का पाउडर मिलाया गया था। तस्करों ने सोना छिपाने के लिए मिल्क पाउडर, ओट्स, अलग-अलग प्रकार के आटे, न्यूट्रला और नारियल दूध पाउडर जैसे सामान्य खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल किया था। सोने के पाउडर को ऐसे

लिया गया है। विशेष सूचना के आधार पर DRI ने मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) की मदद से 23 सितंबर की सुबह दुबई से आए तीनों यात्रियों को रोका। उनके सामान की गहन जांच के दौरान करीब 33.50 किलोग्राम ऐसे खाद्य पदार्थ मिले, जिनमें सोने का पाउडर मिलाया गया था। तस्करों ने सोना छिपाने के लिए मिल्क पाउडर, ओट्स, अलग-अलग प्रकार के आटे, न्यूट्रला और नारियल दूध पाउडर जैसे सामान्य खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल किया था। सोने के पाउडर को ऐसे

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो साप्ताहिक 'सुबह से शाम तक की खबरें' आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनीनोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: Email Id - ssnews2008@gmail.com
या वाट्सएप नं. 8898330400

इंदौर, उज्जैन और चित्तौड़गढ़ स्टेशनों पर ATVM से टिकट लेना हुआ आसान



संवाददाता

रतलाम, मध्य प्रदेश। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट लेने की प्रक्रिया को और सरल, सुविधाजनक तथा केशलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रेलवन ऐप और UTS ऐप के साथ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) के जरिए यात्री अब लंबी कतार में लगे बिना स्वयं अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों की सहायता के लिए इंदौर, उज्जैन और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशनों पर ATVM फैसिलिटेटर भी नियुक्त किए गए हैं। ATVM में QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। यात्री किसी भी UPI-सक्षम ऐप से मशीन पर प्रदर्शित QR कोड स्कैन कर टिकट का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान पूरा होते ही टिकट प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इंदौर रेलवे स्टेशन पर दो, उज्जैन में एक और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ATVM फैसिलिटेटर

नियुक्त किया गया है। फैसिलिटेटर उन यात्रियों की सहायता करेंगे, जिन्हें मशीन से टिकट निकालने में परेशानी होती है या ATVM के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। वे यात्रियों को टिकट निकालकर देने के साथ मशीन इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी समझाएंगे, ताकि भविष्य में यात्री स्वयं टिकट प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था से जहां टिकट काउंटरों पर लंबी कतार और भीड़ कम करने में मदद मिलेगी, वहीं यात्रियों का समय भी बचेगा। रेलवे के मुताबिक इससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। पहले ATVM फैसिलिटेटर के रूप में केवल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना थी, लेकिन इसमें संशोधन के बाद अब आवश्यकता के अनुसार अन्य लोगों को भी फैसिलिटेटर के रूप में शामिल किया जा सकता है। रतलाम मंडल का कहना है कि डिजिटल और स्व-सेवा आधारित टिकटिंग सुविधाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कम समय में आसानी से अनारक्षित टिकट मिल सकें और रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की भीड़ कम हो।

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई: 14.81 करोड़ का 9.40 किलो विदेशी सोना जब्त

संवाददाता

मुंबई। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी के एक अनोखे तरीके का पर्दाफाश किया है। दुबई से मुंबई पहुंचे तीन भारतीय यात्रियों के पास से करीब 14.81 करोड़ मूल्य का 9.40 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया गया। सोने को बारिक पाउडर में बदलकर रोजमर्रा के पैकड फूड प्रोडक्ट्स में मिलाकर छिपाया गया था। तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर

लिया गया है। विशेष सूचना के आधार पर DRI ने मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) की मदद से 23 सितंबर की सुबह दुबई से आए तीनों यात्रियों को रोका। उनके सामान की गहन जांच के दौरान करीब 33.50 किलोग्राम ऐसे खाद्य पदार्थ मिले, जिनमें सोने का पाउडर मिलाया गया था। तस्करों ने सोना छिपाने के लिए मिल्क पाउडर, ओट्स, अलग-अलग प्रकार के आटे, न्यूट्रला और नारियल दूध पाउडर जैसे सामान्य खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल किया था। सोने के पाउडर को ऐसे



खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया गया था जिनका रंग, बनावट और गाढ़ापन उससे मिलता-जुलता था, ताकि सामान्य जांच के दौरान तस्करी पकड़

में न आए। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों से सतिग्ध सामग्री को अलग कर उसकी जांच कराई, जिसके बाद कुल 9.40 किलोग्राम (शेष पेज 2 पर)

ईमानदार ट्रैफिक PI के वसूलीबाज हवलदार! नागपाड़ा में 400 रुपए लेकर छोड़ी बाइक

संवाददाता

मुंबई। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की छवि कुछ वसूलीबाज हवलदारों के चलते धूमिल हो रही है। घटना शनिवार शाम करीब 6.30 बजे की है। मुंबई सेंट्रल से महालक्ष्मी की तरफ आते समय सात रास्ता के सर्कल पर नागपाड़ा ट्रैफिक पुलिस के पांच से छह हवलदार मौजूद थे, जिनमें एक-दो हेड हवलदार और एक महिला हवलदार भी शामिल थीं। महिला हवलदार की नेम प्लेट दिखाई दे रही थी, जिस पर सविता मेश्राम नाम लिखा हुआ था, जबकि बाकी पुलिसकर्मियों ने मोबाइल रखकर अपनी नेम प्लेट छुपा रखे थे। एक हवलदार के पास आईफोन 17 और सैमसंग फोल्ड जैसे महंगे मोबाइल थे। उसने भी मोबाइल से अपनी नेम प्लेट छुपा रखी थी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने सिग्नल जंप करने की बात कहते हुए एक टू-व्हीलर को रोका। चालक हादी अली से लाइसेंस मांगा गया। लाइसेंस दिखाने के बाद गाड़ी का नंबर चेक किया गया और बताया गया कि वाहन पर करीब 13500 हजार रुपये का फाइन है, जिसे भरना होगा। उसी गाड़ी जिले की किसी भी तहसील को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार और अहिल्यानगर (शेष पेज 2 पर)

महिला हवलदार सविता मेश्राम की मौजूदगी में हुई घटना, PI राजेश गायकवाड़ से नहीं हो सकी बात, महिला पुलिसकर्मी गायकवाड़ ने उठाया फोन



फिलहाल 1,000 रुपये का फाइन ले लिया जाए। इसके बावजूद करीब 15 मिनट तक चालक को 1500 रुपए का फाइन भरने का दबाव बनाया जाता रहा। इसी बीच चालक हादी अली पीछे गए और एक पानी पूरी के टरेले वाले को 400 रुपये दिए। इसके बाद उन्होंने पत्रकार से कहा, "चलो, बात बन गई।" एक तरफ पत्रकार पुलिसकर्मियों से लगातार अनुरोध करते रहे, वहीं दूसरी तरफ हवलदारों की टोली ने 400 रुपये लेकर चालक को जाने दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब वाहन पर 13500 रुपये का फाइन बताया जा रहा था तो आखिर 400 रुपये लेकर उसे कैसे जाने दिया गया? ड्यूटी

पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपनी नेम प्लेट मोबाइल से क्यों छुपा रखी थी? इस संबंध में जब नागपाड़ा ट्रैफिक PI राजेश गायकवाड़ से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन महिला पुलिसकर्मी गायकवाड़ ने उठाया। उन्होंने बताया कि सविता मेश्राम उनकी स्टाफ में हैं। हालांकि PI राजेश गायकवाड़ से सीधे बातचीत नहीं हो सकी। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि गणपति विसर्जन के चलते रात की ड्यूटी करने के बाद PI गायकवाड़ घर गए हैं और उनका फोन बताया जा रहा था तो आखिर 400 रुपये लेकर उसे कैसे जाने दिया गया? ड्यूटी

संपादकीय

चुनाव आयोग के सामने भरोसे की चुनौती

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल समय पर चुनाव कराने से नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया पर नागरिकों के भरोसे से भी तय होती है। इसी कारण चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद विपक्ष ने आयोग के कामकाज पर लगातार सवाल उठाए हैं। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आयोग की आलोचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सुचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और आयोग के भीतर कथित मतभेदों से जुड़े घटनाक्रम ने बहस को नया आधार दिया है। हाल में इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच आयोग से जुड़े विभिन्न निर्णयों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने, फॉर्म-6 से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा और मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण जैसे विषय शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग का पक्ष है कि वैधानिक निर्णय तीनों सदस्यों की सहमति से लिए गए और फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि एसआईआर से संबंधित एक अलग घोषणा जोड़ी गई थी।

लोकतांत्रिक संस्था के भीतर अलग-अलग विचार होना अपने आप में असामान्य नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण मामलों पर विमर्श किसी संस्था की निर्णय प्रक्रिया को अधिक मजबूत बना सकता है। चिंता तब पैदा होती है जब मतदाता के अधिकार से सीधे जुड़े फैसलों की प्रक्रिया और उनके कानूनी आधार को लेकर आयोग के सदस्यों के बीच ही सवाल उठें। ऐसे मामलों में अस्पष्टता के बजाय अधिक पारदर्शिता ही संस्था की विश्वसनीयता मजबूत कर सकती है। विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू फॉर्म-6 से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक एसआईआर के दौरान नए मतदाताओं से यह बताने वाली अतिरिक्त घोषणा मांगी गई कि उनका, उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में था या नहीं। चुनाव आयुक्तों की आपत्ति इस बात पर थी कि वैधानिक फॉर्म से जुड़ी ऐसी आवश्यकता को किस प्रक्रिया के तहत लागू किया गया। चुनाव आयोग ने बाद में स्पष्ट किया कि मूल फॉर्म-6 में परिवर्तन नहीं किया गया और संबंधित जानकारी अलग घोषणा के माध्यम से मांगी गई। लेकिन तकनीकी और कानूनी बहस से अलग आम मतदाता की व्यावहारिक परेशानी को भी समझना जरूरी है। दशकों पुरानी मतदाता सूची में अपने माता-पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों की जानकारी तलाशना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। प्रवासी मजदूरों, किसानों के मकानों में रहने वाले परिवारों, बुजुर्गों और बार-बार स्थान बदलने वाले नागरिकों के लिए यह काम और कठिन हो सकता है। चुनाव सुधार की कोई भी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें पात्र मतदाता के लिए पंजीकरण आसान हो, न कि अनावश्यक रूप से जटिल। एसआईआर का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहराव वाली अथवा अन्य अपात्र प्रविष्टियों को सूची से हटाना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। लेकिन इसी के साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न हटे। मतदाता सूची की शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी लक्ष्य नहीं हैं; दोनों को साथ लेकर चलना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी बड़ी संख्या में अपीलें ने इसी चुनौती को सामने रखा है। हाल की अदालती कार्यवाही में लाखों लंबित अपीलों और उनके निस्तारण की गति को लेकर सवाल सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा गति से मामलों के निपटारे में वर्षों लगने की आशंका जताई गई, जिसके बाद अधिक डिब्बूनल की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई है।वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन मामलों में अपीलों पर फैसला हो चुका है, उनमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वापस बहाल किए गए हैं। यह तथ्य दो बातें रेखांकित करता है—अपील की व्यवस्था महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक स्तर पर हुई संभावित त्रुटियों को शीघ्र सुधारने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है। मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाना सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं है। यदि कोई पात्र नागरिक चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाता तो बाद में नाम बहाल हो जाने पर भी उस चुनाव में उसके खोए हुए मताधिकार की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए आम हटाने की प्रक्रिया में सूचना, सुनवाई और अपील का अधिकार व्यावहारिक रूप से प्रभावी होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पूरे विवाद को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित मानकर नहीं देखना चाहिए। विपक्ष के आरोपों की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है और आयोग का अपना स्पष्टीकरण है। लेकिन संस्था के भीतर दर्ज आपत्तियों और मतदाता सूची से जुड़े इतने व्यापक प्रश्नों का उत्तर दस्तावेजों, स्पष्ट नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से देना ही सबसे प्रभावी रास्ता होगा।

आयोग चाहे तो महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार, प्रक्रियागत बदलाव और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के मामलदों के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। इससे न केवल राजनीतिक विवादों को तथ्यों की कसौटी पर परखा जा सकेगा, बल्कि आम नागरिक को भी यह समझने में आसानी होगी कि उसके मताधिकार से जुड़े निर्णय किस आधार पर लिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की जवाबदेही किसी सरकार या विपक्ष के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और देश के मतदाताओं के प्रति है।

जमूई की घटना और सार्वजनिक संवेदना का संकट

रंजीत विद्यार्थी

महाभारत में दौड़दी के अपमान का प्रसंग भारतीय स्मृति में केवल एक स्त्री के साथ हुए अन्याय की कथा नहीं है, वह उस सभा की चुप्पी का भी स्मरण करता है जिसमें अन्याय सामने था और हस्तक्षेप का साहस कमजोर पड़ा। जमूई की घटना की तुलना उस प्रसंग से करना उचित नहीं होगा। दोनों के संदर्भ और परिस्थितियां अलग हैं। फिर भी यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब किसी के साथ सार्वजनिक रूप से अन्याय होता दिखाई दे, तब वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी क्या है?यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे हाथ में कैमरा पहले पहुंचता है और मदद का हाथ बाद में। मोबाइल फोन ने घटनाओं को दर्ज करना आसान बना दिया है। इससे अपराध के प्रमाण जुटाने और जांच में सहायता मिलने की संभावना भी बढ़ी है। लेकिन वही कैमरा किसी पीड़ित को पीड़ा को तमाशे में बदल सकता है, यदि रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति सहायता पहुंचाने के बजाय केवल दृश्य को साझा करने की जल्दी में हो। किसी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप में गलत नहीं है। कई बार यही रिकॉर्डिंग न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनती है। समस्या तब पैदा होती है जब वीडियो बनाने का उद्देश्य साक्ष्य सुरक्षित करना नहीं, बल्कि उसे मनोरंजन, सनसनी या शोख मीडिया पर प्रसार का माध्यम बनाना हो। पीड़ित की पीड़ा को ‘कंटेंट’ में बदल देने की प्रवृत्ति समाज के भीतर संवेदना के एक नए संकेट की ओर संकेत करती है। सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार की गति को अभूतपूर्व बना दिया है। कोई घटना कुछ

मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन सूचना की गति और जिम्मेदारी की गति एक जैसी नहीं हुई है। हम वीडियो आगे भेजने में जितने तेज हैं, उतनी तेजी से पुलिस, परिवार या संबंधित सहायता तंत्र को सूचना देने में हमेशा सक्रिय नहीं होते। यहां नागरिक जिम्मेदारी का सवाल सामने आता है। किसी अपराध या हिंसा को अपनी आंखों के सामने होते देखना हर व्यक्ति से नायक बनने की अपेक्षा नहीं करता। हर व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करना सुरक्षित भी नहीं हो सकता। लेकिन मदद के दूसरे रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। जैसे-पुलिस को सूचना देना, अस्पास के जिम्मेदार लोगों को बुलाना, आपात सहायता मांगना, पीड़ित को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहायता करना और घटना से जुड़े प्रमाण को सुरक्षित रखना। इस फर्क को समझना जरूरी है कि हस्तक्षेप का अर्थ हमेशा भीड़ से भिड़ जाना नहीं है। कई बार एक फोन कॉल भी हस्तक्षेप है। किसी बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाना हस्तक्षेप है। किसी महिला को अकेला न छोड़ना हस्तक्षेप है। अपराधी की पहचान और घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना भी नागरिक जिम्मेदारी है। इसके उलट,भीड़ का केवल दर्शक बन जाना कई सवाल खड़े करता है। भीड़ में व्यक्ति अक्सर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दूसरों के बीच बांट देता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यही मनोविज्ञान कई बार ऐसी परिस्थितियों को और गंभीर बना देता है। सामने मौजूद लोग घटना देखते रहते हैं, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाता। आज इसमें मोबाइल फोन ने एक नया आयाम

पेज 1 का शेष ममता बनर्जी की...

सितंबर को श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में ममता बनर्जी की सभा की अनुमति दी थी, लेकिन अधिकतम एक हजार लोगों की सीमा सहित कई शतें लगाई थीं। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को सभा के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था। सभा से पहले तुणमूल नेताओं ने पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें कार्यक्रम में पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस कार्रवाई और सभा को लेकर दोनों पक्षों के

पुस्तक चर्चा: काश! मैं बादल होता

विवेक रंजन श्रीवास्तव
कविता के लिए हमेशा किसी असाधारण घटना की जरूरत नहीं होती। एक खाली मेज़, उड़ती पतंग, पहली बारिश की खुशबू, किसी मित्र की स्मृति या मन में उठती कोई छोटी-सी शिकायत भी कविता का कारण बन सकती है। आशुतोष झुड़ेले ‘ओ रे कबीरा’ का संग्रह ‘काश! मैं बादल होता’ इसी सहज अनुभूति से निकली 51 कविताओं का संसार है। कवि स्वयं स्वीकार करता है कि ये कविताएँ जीवन के उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख, त्योहारों, घटनाओं और रोजमर्रा के अनुभवों से बनी हैं। इस संग्रह को पढ़ते हुए लगता है कि कवि कविता लिखने से अधिक जीवन को पकड़ने की कोशिश करता है। ‘बगीचे की मेज़’ इसका सुंदर उदाहरण है। सामान्य-सी दिखाई देने वाली एक मेज़ कवि की दृष्टि में अनेक जीवन-कथाओं की साक्षी बन जाती है। वहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेमी युगल हैं, अकेलेपन की तलाश में आए लोग हैं और अपने हिस्से के लिए संघर्ष करते चेहरे भी। अंततः वही मेज़ खाली होती है और कवि को लगता है, “यहीं तो मेरी मुलाकात आज उम्मीद से होने वाली है।” वस्तु को जीवन के रूपक में बदल देना इस कविता की उपलब्धि है। संग्रह में स्मृति एक महत्वपूर्ण संवेदनात्मक आधार है। ‘चुरा ले गए’ में कवि उन चीजों की तलाश करता है जो आधुनिक जीवन में धीरे-धीरे हमसे छूटती जा रही हैं, सुबह की ताजगी, शाम की सादगी, पहली बारिश की खुशबू, बगीचे के फूल और आँगन की मिट्टी। “कुछ लोग पहली बारिश की खुशबू चुरा ले गए” केवल एक सुंदर बिंब नहीं, संवेदनाओं के क्षरण की ओर बाढ़ संकेत है। इसी क्रम में ‘पतझड़ के भी रंग होते हैं’ जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी सौंदर्य खोजती है। पतझड़ यहाँ अंत नहीं, देखने की नई दृष्टि है। सूखे पत्तों, गिरे फूलों और पुराने गीतों में भी रंग और स्मृति बची हुई है। यह कविता संग्रह के आशावादी स्वर को पहचान देती है। ‘पतंग सी जिंदगी’ में जीवन की उड़ान और उसकी डोर का सुंदर साम्य है। पतंग दूर जाती है, लौटती है, हवा से संघर्ष करती है, फिर भी डोर से जुड़ी रहती है। स्वतंत्रता और संबंधों के बीच मनुष्य की स्थिति को कवि ने एक परिचित लोक-प्रतीक में सहजता से बाँधा है। आशुतोष की कविता केवल निजी अनुभवों तक सीमित नहीं रहती। ‘भीड़ की आड़ में’ सामाजिक विडंबनाओं पर

सुबह से शाम

तक की खबरें



तीखा प्रश्न करती है। धर्म, जाति और सामूहिक पहचान के पीछे छिपकर मनुष्य अपने दोषों से बचने की कोशिश करता है। कविता का निष्कर्ष आत्मसंशय की ओर ले जाता है,दोष किसी भीड़ का नहीं, अंततः मनुष्य का अपना है। ‘हम सोचते हैं’ इसी तेवर को व्यंग्य में बदलती है और हमारी सामाजिक स्मृति तथा आत्ममुग्धता पर चोट करती है। ‘दर दर गंगे’ में सांस्कृतिक आस्था और पर्यावरणीय चिंता साथ दिखाई देती हैं। गंगोत्री से गंगासागर तक की यात्रा में कवि उस नदी की पीड़ा दर्ज करता है जिसे हम माँ कहते हैं, जिसकी आरती करते हैं, पर जिसकी रक्षा का दायित्व भूल जाते हैं। “बहाती जा रही बस आँसू” जैसे बिंब श्रद्धा को जिम्मेदारी से जोड़ देते हैं। इस तरह के कई नवाचारी रूपक कवि की अनुभव जन्म भाषा ,भाव , शब्द सामर्थ्य के परिचायक हैं। यद्यपि यह कवि की पहली ही कृति है, उनके व्यक्तित्व की तरह व्यापक सुगठित सरल तथा परिपक्व है।

‘भोपाल’ संग्रह की अत्यंत छोटी, किंतु गहरी कविता है। “हवा क्या होती है, पूछो भोपाल से” जैसे लगातार प्रश्न एक त्रासदी को केवल घटना न रहने देकर सामूहिक स्मृति में बदल देते हैं। शब्द कम हैं, लेकिन उनके पीछे भय, अन्याय और जीवन-मृत्यु का पूरा अनुभव उपस्थित है। भोपाल गैस त्रासदी पर केंद्रित यह कविता महत्वपूर्ण संवेदी, दस्तावेजी रचना बन पड़ी है। रिशतों की नाजुकता भी कवि की प्रमुख चिंता है। ‘डोर’ में समय और संबंध दोनों को ऐसे धागे की तरह देखा गया है जो लंबा होने पर अपना सिरा खो देता है और तनिक से झटके में टूट भी सकता है। ‘रिशते’ कविता अपेक्षा और उपेक्षा के बजाय देने और कर्म को महत्व देती है। ‘शिकायत थी मुझको’ में शिकायतों की पूरी सूची अंततः आत्मबोध सामने लाती है। कबीरा का मुस्कुराकर



संवेदनशीलता, बाल सुरक्षा और डिजिटल व्यवहार पर गंभीर बावचीत की जरूरत है। बच्चों और युवाओं को यह समझना होगा कि किसी की पीड़ा का वीडियो बनाना और उसे साझा करना हमेशा जागरूकता नहीं होता। व्यस्क समाज के सामने भी यही सवाल है। हम बच्चों से संवेदनशील होने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं सोशल मीडिया पर किसी दुर्घटना, हिंसा या अपमानजनक घटना को देखते हैं। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल खबर पहुंचाने तक सीमित नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि खबर किस तरह पहुंचाई जा रही है और उससे पीड़ित को कोई अतिरिक्त नुकसान तो नहीं हो रहा। जमूई की घटना को लेकर समाज में उठे सवालों का एक हिस्सा कानून और पुलिस की भूमिका से जुड़ा है। गंभीर आरोपों की पीड़ित को सार्वजनिक तमाशा बनाना उद्देश्य निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ समाज की अपनी जिम्मेदारी को भी अलग नहीं किया जा सकता। पुलिस हर सड़क, हर गली और हर खण मौजूद नहीं हो सकती। नागरिकों की सक्रणता और संवेदनशीलता सार्वजनिक सुरक्षा की पहली सामाजिक परत है।यहां शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को कानून, अधिकार और परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हैं, लेकिन संकट की स्थिति में क्या करना चाहिए, यह कम सिखाते हैं। विद्यालयों में नागरिक जिम्मेदारी, लैंगिक

बीच पहले से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तुणमूल गुट आगामी चुनावी मुकाबले में नए ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव विह्व के साथ अपनी पहचान मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह चिह्न पार्टी में विभाजन के बाद पारंपरिक ‘फूल और घास’ चिह्न के इस्तेमाल को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच सामने आया है। कुणाल घोष की कार पर हुए हमले ने श्रीरामपुर की राजनीतिक तनातनी को और बढ़ा दिया है। फिलहाल सबसे अहम सवाल हमलावरों की पहचान और घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। कुणाल घोष और तुणमूल ने भाजपा पर आरोप लगाया है, जबकि भाजपा इससे इनकार कर रही है; ऐसे में जिम्मेदारी का निर्धारण पुलिस जांच और उपलब्ध

वीडियो/CCTV साक्ष्यों के आधार पर होना बाकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले महीने की छह तारीख यानी 6 अक्टूबर, 2026 को नंदीग्राम और रेंजीनगर की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। राज्य में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। राज्य में सतारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस और ऋतवत बनर्जी के नेतृत्व वाले तुणमूल कांग्रेस (TMC) के गुट ने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है।

मुंबई एयरपोर्ट पर...

विदेशी सोना बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 14.81 करोड़ बताई गई है। सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के संबंधित प्रावधानों के तहत जन्त किया गया है। पूछताछ के दौरान तीनों यात्रियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे एक ही संगठित सोना तस्करी सिंडिकेट के लिए कूरियर के रूप में काम कर रहे थे। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर DRI ने सिंडिकेट की पहचान कर ली है और अब उसके पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि दुबई में सोना इकट्ठा करने, उसे पाउडर में बदलकर खाद्य पदार्थों में छिपाने और मुंबई तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था में कौन-कौन शामिल था। मुंबई पहुंचने के बाद तस्करी का सोना लेने और आगे पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस कार्रवाई से सोना तस्करी का नया तरीका सामने आया है, जिसमें कीमती धातु को पाउडर बनाकर सामान्य पैकड फूड प्रोडक्ट्स में मिला दिया गया। DRI अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस सिंडिकेट ने इससे पहले भी इसी तरीके से सोने की तस्करी की थी और इस नेटवर्क के जरिए कितनी खेप भारत लाई जा चुकी है।

राज्य के 265 तहसीलों...

जिलों के कुल 49 तहसील तथा पुणे, सोलापुर, सांगली, सातारा और कोल्हापुर जिलों के 35 तहसील इसमें शामिल हैं। इसी तरह छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी और हिंगोली जिलों के 74 तहसीलों में प्रथम चेतावनी लागू की गई है। अमरावती विभाग के बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम और यवतमाल जिलों के 56 तहसील तथा नागपुर विभाग के वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरोली जिलों के 39 तहसील भी इसके दायरे में आए हैं।

फसल नुकसान की आर्थिक सहायता के लिए आएका अलग शासन निर्णय
फसल नुकसान के लिए किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की घोषणा अभी अलग से की जाएगी। सरकार के अनुसार पंचनामा और फसल की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अलग शासन निर्णय जारी कर सहायता की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हाल ही में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों के खेतों में जाकर स्थिति देखी थी और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी थीं। सरकार का कहना है कि अब पंचनामा और सटीक सर्वेक्षण को प्राथमिकता देते हुए किसानों, विद्यार्थियों, खेतिहर मजदूरों और आम नागरिकों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

ईमानदार ट्रैफिक PI के...

सामने नहीं आ सका। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा, लेकिन उनके अधीन फील्ड में तैनात हवलदारों की इस कार्यप्रणाली ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि PI राजेश गायकवाड इस मामले की जानकारी मिलने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुखिया सह पुलिस आयुक्त सत्य नागरण चौधरी हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरह की वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? क्या नागपाड़ा के सात रास्ता पर मौजूद CCTV फुटेज और उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जांच की जाएगी?



मेघ राशि: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। अटका हुआ पैसा मिलने अथवा आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्याकुशलता की सराहना होगी। कारोबारियों को पुराने ग्राहक या संपर्क से लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि: सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता के साथ हो सकती है। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने के बावजूद आप अपनी सुझबुझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने के संकेत हैं।

कर्क राशि: इस सप्ताह धैर्य और व्यावहारिक सोच आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से काम का दबाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से बचें। व्यापार में किसी बड़े निवेश या समझौते से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह प्रगति और प्रतिक्रिया बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है और पुराने संपर्कों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे।

कन्या राशि: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह नए अवसरों का संकेत दे रहा है। नौकरी में बदलाव चाहने वालों को सकारात्मक खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की पहचान बनेगी। व्यापार में नए ग्राहक या नया समझौता लाभकारी हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी पुराने मतभेद का समाधान होगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं।

वृश्चिक राशि: इस सप्ताह सोच-समझकर काम उठाना लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण जानकारीयों को लेकर सावधान रहें। कारोबार में सप्ताह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। अचानक धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चले। पारिवारिक मामलों में क्रोध से बचना जरूरी होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं। व्यवसाय में दूर के संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। काम से जुड़ी यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह मेहनत के अनुरूप परिणाम देने वाला रहेगा। शुरुआती दिनों में काम अधिक रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य से स्थितियां बेहतर होंगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में पुराना भुगतान मिलने या नया प्रस्ताव आने की संभावना है।

कुंभ राशि: सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होइस सप्ताह नए विचार और योजनाएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। कारोबार में तकनीक या नई कार्यप्रणाली अपनाने से लाभ होगा।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। लंबे समय से लंबित किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के योग है। कारोबार में नया समझौता लाभदायक साबित हो सकता है।

सूखे से प्रभावित किसानों को सरकार नहीं छोड़ेगी बेसहारा: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

संवाददाता
नांदेड। बारिश में लंबे अंतराल के कारण राज्य में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को खेतों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पंचनामा करने के निर्देश दिए हैं। पंचनामे और निरीक्षण के आधार पर नुकसानग्रस्त किसानों को सहायता दी जाएगी। “सरकार किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ेगी,” यह भरोसा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने दिया। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने शनिवार को नांदेड जिले के सोमखेड और लोहा में फसलों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील, विधायक विक्रम काळे, प्रताप पाटील चिखलीकर और आनंद तिडके-बोडारकर, जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील सहित कृषि एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पवार ने कहा कि बारिश नहीं होने से खेतों में फसलें सूख गई हैं और किसानों की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, “मैं खुद मराठवाड़ा की बेटी हूं और यहां की सूखे की स्थिति को अच्छी तरह जानती हूं।” सरकार ने किसानों की भावनाओं और परेशानियों को गंभीरता से लिया है।

नांदेड के सोनखेड और लोहा में फसलों का किया निरीक्षण, पंचनामे के आधार पर मिलेगी मदद, पात्र किसानों को कर्जमाफी का भी लाभ



प्रशासन को प्रत्यक्ष निरीक्षण और पंचनामे के निर्देश दिए गए हैं तथा जिस किसान का जितना और जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, उसी के अनुसार सहायता दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। सूखे की स्थिति में किसान परिवारों के लिए पाने का पानी, पशुओं के लिए पानी और चारा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि

सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और नुकसानग्रस्त किसानों को जल्द सहायता दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान सुनेत्रा पवार ने किसानों और महिला किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है और हरसंभव सहायता की जाएगी। इस के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध और नागरिक मौजूद रहे।

1 अक्टूबर से ST की रियायती यात्रा के लिए NCMC कार्ड अनिवार्य

संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (S.T.) की विभिन्न रियायती योजनाओं का लाभ लेने वाले अमृत वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) अनिवार्य किया जाएगा। रियायती टिकट जारी करते समय NCMC कार्ड के इस्तेमाल का निर्णय एसटी महामंडल ने लिया है। इसके लिए राज्यभर के एसटी डिपो और बस स्टेशनों पर कार्ड पंजीकरण एवं वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसटी महामंडल सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न सामाजिक वर्गों को रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा देता है। इसमें अमृत वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और महिला यात्रियों

को मिलने वाली यात्रा रियायत भी शामिल है। इन रियायतों के प्रबंधन का अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए NCMC कार्ड प्रणाली लागू की जा रही है। 1 अक्टूबर से रियायती टिकट NCMC कार्ड के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। जिन यात्रियों के पास सक्रिय (Active) NCMC कार्ड होगा या कार्ड के लिए पंजीकरण कराने के बाद मिली QR कोड वाली रसीद होगी, उन्हें रियायती यात्रा का लाभ मिलेगा। NCMC कार्ड के लिए पंजीकरण कराने वाले अमृत वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और महिला यात्री QR कोड वाली रसीद को बस कंडक्टर की ETM मशीन पर स्कैन करकर रियायती टिकट प्राप्त कर सकेंगे। यह पंजीकरण रसीद 30 दिनों तक मान्य रहेगी। इस अवधि के भीतर

यात्रियों को अपना NCMC कार्ड एक्टिव कर उसमें टॉप-अप करना आवश्यक होगा। NCMC कार्ड के पंजीकरण और वितरण के लिए ई-बिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एसटी बस स्टेशनों एवं डिपो के साथ डिपो की सीमा से बाहर भी अधिकृत एजेंट नियुक्त किया गया है। इससे यात्रियों को नजदीकी अधिकृत केंद्र पर कार्ड पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। कार्ड में राशि डालने के लिए BHIM App से Top-up करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। NCMC कार्ड के पीछे दिए गए QR कोड को BHIM App से स्कैन कर यात्री टॉप-अप कर सकेंगे। जिन पात्र लाभार्थियों को आधार कार्ड के बायोमेट्रिक में उंगलियों के निशान नहीं मिलने के कारण पंजीकरण में परेशानी होती है, उनके लिए भी

वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को कार्ड या QR कोड वाली पंजीकरण रसीद दिखानी होगी, 30 दिन तक मान्य रहेगी रसीद



वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे यात्री आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए NCMC कार्ड का पंजीकरण करा सकेंगे। एसटी महामंडल ने अमृत वरिष्ठ

वसई विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व

मुख्य कार्यालय- विरार, दूरध्वनी- ९५२५०- २४०२१७९/२४०३४४२/२४०२५६३

जा.क्र. वविशमा/कर/१११५ /२०२६-२७ दि.२१/०९/२६

जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६९ अन्वये जाहीर नोटीस खालील मालमत्तेच्या हस्तांतरण संबंधाने वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय नालासोपारा येथे प्राप्त झालेल्या मालमत्ता धारकाच्या प्रकरण परत्वे नोटीसत्यानुसार सदर हस्तांतरण संदर्भात कोणत्याही हितसंबंधाने हरकत अगर आक्षेप असल्यास हि नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत हितसंबंधाच्या व हरकतीच्या लेखी पुराव्यासह वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय विभागीय कार्यालय विरार येथे लेखी स्वरूपात हरकत नोंदवावी अन्यथा करवसुलीच्या सोयीसाठी सदर हस्तांतरण करून महानगरपालिका दफ्तरी याबाबतची नोंद घेतली जाईल.

अ.क्र.	मालमत्ता क्र.	पावती क्र.	ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजे मालमत्ता विकणाऱ्याचे नाव किंवा अभिहस्तांकन कत्यांचे नाव	खरेदीदाराचे किंवा अभिहस्तांकन नाव
1	VR06/2351/28	43060	प्राजक्ता परशुराम करंजकर / मिहिर परशुराम करंजकर	धोंडू धावडे / प्रसाद धोंडू धावडे
2	VR06/1623/111	43061	आशा राजेश गुप्ता	विधाता सदानंद मुणगेकर
3	VR06/2188/10	43050	श्री साई पंटरप्रायजेस	तुषार ताराचंद बंगाल
4	VR06/2326/7	43316	विकास नगरी डेव्हलपर्स	शुभांगी विजय धनुषारी
5	VR06/2171/12	43056	दिपीका दीपक पालवे	प्रेरणा प्रविण धावडे
6	VR06/1630/25	43054	दिपीका दत्तात्रय नाईक / पराग द.नाईक	जान्हवी महेश पिंपळे
7	VR06/1646/4	43055	दिलीपकुमार दिपचंद गुप्ता	उपेंद्र धन्नुलाल गुप्ता
8	VR06/1835/46	43053	मनिषा रामचंद्र कांबळे	राकेश सपत दुपटे
9	VR06/2305/4	43052	सागर सुरेश जाधव	सुनिल शांताराम मालप
10	VR06/1549/15	41810	चंद्रशेखर गजानन वैद्य	कुंदन दत्ताराम देवकड
11	VR06/1465/137	41548	सुरेश दानाराम बिर्जे	मेघना महेश थोरे
12	VR06/2326/46	41023	विकास नगरी डेव्हलपर्स	अमर महादेव देसाई
13	VR06/1493/25	41022	गुलाब लौटन प्रजापती	मनोज धोंडु दळवी / मयुरी मनोज दळवी
14	VR06/2122/11	41541	ऋतिका रमेश नाईक	प्रथमेश सुरेश ठोंबरे
15	VR06/2311/32	41547	अक्षय दत्ताराम ठोंबरे	ऋतिक दत्ताराम ठोंबरे
16	VR06/1785/37	43932	प्रकाश बाळकृष्ण केसरकर / प्रतिभा पी.केसरकर	तुषार प्रकाश केसरकर / लिजा प्रकाश केसरकर
17	VR06/2330/31	42585	शिवप्रकाश रामधनी पटेल	संजय रत्नाकर घेवडे
18	VR06/2028/74	40934	रूपेश विजय मोहिते	संकेत सूर्यकांत रामाणे
19	VR06/2203/3	43783	महेश प्रकाश लाजवळ	सुशांत सुरेश होरांबे
20	VR06/2291/5	44826	महेश प्रकाश लाजवळ	प्रणित एकनाथ कुडे

सही/-

सह. आयुक्त

प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व

वसई विरार शहर महानगरपालिका

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने किया अभिवादन

संवाददाता
मुंबई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मंत्रालय में कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने उनके चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर



सामान्य प्रशासन विभाग के कक्ष अधिकारी दत्तात्रय शिंदे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्र. प्र. कोपांडे, सुनील जाधव सहित मंत्रालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

VVMC अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा मुफ्त पौष्टिक भोजन

संवाददाता
पालघर। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत भर्ती मरीजों को राहत देते हुए वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) ने मुफ्त पौष्टिक भोजन, नाश्ता और चाय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई आम सभा की बैठक में इस व्यवस्था के लिए 3.20 करोड़ के खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वसई-विरार क्षेत्र में फिलहाल 7 अस्पताल, 2 मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र, 21 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 बालासाहेब ठाकरे ‘आपला क्लिनिक’ और 45 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पात्र भर्ती मरीजों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन महानगरपालिका के अधिकांश अस्पतालों में कैंटीन की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होने से उनके स्वास्थ्य और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए

3.20 करोड़ के प्रस्ताव को आम सभा की मंजूरी, स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाएगी भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी



महानगरपालिका ने मुफ्त भोजन और नाश्ते की व्यवस्था करने का प्रस्ताव तैयार किया। स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष नीलेश देशमुख ने कहा कि महानगरपालिका अस्पतालों में आने वाले ज्यादातर मरीज कमजोर आर्थिक वर्ग से होते हैं और उनके लिए बाहर से भोजन मंगाना या उसकी व्यवस्था करना मुश्किल होता है। विपक्ष के नेता मनोज पाटिल ने फैसले का स्वागत करते हुए भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है, लेकिन प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता और निश्चित मानकों की सख्ती से निगरानी करनी

चाहिए। महापौर अजीव पाटिल ने भोजन वितरण व्यवस्था को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि एक ही स्थान पर भोजन तैयार कर सभी अस्पतालों में पहुंचाने से दूरी के कारण देरी हो सकती है और मरीजों तक ठंडा भोजन पहुंचने की आशंका रहेगी। इसलिए प्रत्येक अस्पताल के आसपास स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) अथवा स्थानीय संस्थाओं को ताजा भोजन तैयार करने और उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी जाए। भोजन की गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था VVMC स्वास्थ्य समिति की निगरानी में संचालित की जाएगी।

फॉलोअर्स के मामले में शाहरुख खान से आगे निकले बिग बी

मुंबई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बॉलीवुड के दिग्गज और बड़े स्टार हैं हिंदी सिनेमा की। उनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। हाल ही में एम3एम हरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 आई थी जिसमें पता चला कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। स्टार्स की नेटवर्थ के अलावा इसमें उनके सोशल मीडिया फॉलोइंग के बारे में भी बताया है। हालांकि बिग बी और शाहरुख के बीच का डिफ्रेंस काफी कम है। बिग बी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम, लिंकडिन और एक्स(ट्विटर) के हिसाब से एक्टर की फॉलोइंग 4.87 करोड़ है की मिलाकर। शाहरुख की वहीं तीनों प्लेटफॉर्म की



मिलाकर 4.86 करोड़ है। दोनों के बीच सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स का डिफ्रेंस है। ऋतिक रोशन भी इनके काफी करीब हैं। उनके तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4.81 करोड़ है। करण जोहर फिर अगले लंबर पर हैं 1.82 करोड़ फॉलोइंग के साथ। एम3एम हरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 की स्क्रीन और स्पोर्ट कैटेगरी



के मुताबिक शाहरुख खान और उनके परिवार की नेटवर्थ 10 हजार करोड़ है। इस नेटवर्थ के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। वहीं अमिताभ और उनके परिवार की टोटल नेटवर्थ 4 हजार करोड़ है। सलमान खान की वहीं 3000 करोड़ नेटवर्थ है। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर ऋतिक रोशन।

महिलाओं की सुरक्षा और कपड़ों पर ‘पुलिसिंग’ को लेकर कृति सेनन ने उठाए सवाल

अभिनेत्री बोलें— यह ‘पुरुष बनाम महिला’ की लड़ाई नहीं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर समाज की प्रतिक्रिया और सोच पर भी साधा निशाना

मुंबई। अभिनेत्री कृति सेनन ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, पितृसत्ता और उनकी पसंद को लेकर की जाने वाली ‘पुलिसिंग’ पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जेंडर से जुड़ी बहस को केवल ‘पुरुष बनाम महिला’ के रूप में देखना सही नहीं है। उनकी यह प्रतिक्रिया जमुई में छात्राओं से कथित उत्पीड़न के मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सामने आई है। कृति सेनन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें जेंडर से जुड़े मुद्दों को पुरुषों और महिलाओं के बीच टकराव के रूप में पेश किए जाने पर सवाल उठाया गया। साझा की गई पोस्ट में कहा गया कि यह लड़ाई

पुरुषों के खिलाफ नहीं, बल्कि पुरुष-प्रधान और महिला विरोधी सोच के खिलाफ है। इसमें उन महिलाओं की मानसिकता पर भी सवाल उठाया गया, जो पितृसत्तात्मक सोच को संस्कार मानकर स्वीकार करती हैं। कृति ने एक अन्य पोस्ट का भी समर्थन किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों और अभिनेत्रियों के कपड़ों को लेकर समाज में दिखाई देने वाली अलग-अलग प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाए गए थे। पोस्ट में कहा गया कि बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज हत्या जैसी घटनाओं की तुलना में कई बार किसी अभिनेत्री के कपड़ों को लेकर अधिक नाराजगी दिखाई जाती है और यह समाज की प्राथमिकताओं



पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा कृति ने एक और स्टोरी साझा करते हुए महिलाओं को ही हिंसा से बचने के तरीके सिखाए जाने की मानसिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर महिलाओं को यह बताना कब बंद किया जाएगा कि वे मारपीट और उत्पीड़न से कैसे बचें और पुरुषों को यह सिखाना

कब शुरू किया जाएगा कि महिलाओं पर हमला, उन्हें परेशान, भयभीत या नियंत्रित नहीं करना चाहिए। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों का जिक्र करते हुए, कृति ने पीड़ित से ही सवाल किए जाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी बच्चे के साथ अपराध होने पर अपराध करने वाले की मानसिकता और कृत्य पर सवाल उठाने के बजाय आज भी यह क्यों पूछा जाता है कि पीड़िता ने क्या पहना था, वह कहाँ थी, किसके साथ थी या उसे बाहर जाने की अनुमति क्यों दी गई थी। कृति सेनन की इन सोशल मीडिया पोस्टों ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहराने वाली सोच, महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी और समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक मानसिकता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

गोविंदा और कोमल रानी फिर सुर्खियों में, सुनीता आहूजा की टिप्पणियों पर अभिनेत्री का तीखा पलटवार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों मुंबई के लालबागवा राजा पंडाल में साथ नजर आए, जिसके बाद उनके कथित रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इसी बीच कोमल रानी स्वर्णकार ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की ओर से की गई कथित टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपना पक्ष रखा है। शनिवार, 26 सितंबर को कोमल रानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोमल ने लिखा, “जो औरत अपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर

रही हो, ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगती। पहले से टूटे हुए घर में कोई कभी घर तोड़ने वाला नहीं हो सकता।” ये कोमल रानी के आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कोमल ने आगे कहा कि किसी महिला के दर्द को समझने और उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे सार्वजनिक रूप से सामने लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह सवाल उठता है। उन्होंने सवाल किया कि यह वास्तव में दर्द है या कोई सोची-समझी रणनीति। अपनी पोस्ट में कोमल ने किसी व्यक्ति को लगातार मानसिक रूप से परेशान करने, काम करने से रोकने, अकेला कर देने और उसकी

लालबागवा राजा पंडाल में साथ दिखने के बाद रिश्ते को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा, कोमल बोलें—“अपने एजेंडे के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो”

स्थिति बिगाड़ने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने लिखा, “मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है।” इसके साथ ही उन्होंने कहा, “अपने एजेंडे के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो।” गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते की चर्चाओं ने उस समय और जोर पकड़ा था, जब दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। इसके बाद सुनीता आहूजा की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी।

दिए गए विवरण के मुताबिक, सुनीता ने कोमल को अपनी बेटी की उम्र की बातें बताते हुए गोविंदा के लिए “शुगर डेडी” जैसी टिप्पणी की थी। वहीं गोविंदा ने भी अपने खिलाफ चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री का एक खास समूह उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कम उम्र की अभिनेत्री के साथ काम करने के फैसले का बचाव किया और सुनीता को सार्वजनिक रूप से उन्हें बदनाम करने से बचने की बात कही थी।



खनन अधिकारी के सरकारी आवास से मिला नोटों का खजाना, 63 लाख नकद बरामद

संवाददाता
शामली, उत्तर प्रदेश। जिला खनन अधिकारी के सरकारी आवास पर विजिलेंस की कार्रवाई में नकदी का ऐसा खजाना सामने आया, जिसे देखकर जांच टीम के सदस्य भी हैरान रह गए। सरकारी आवास की तलाशी के दौरान दो अलमारियों से लाखों रुपये बरामद हुए। एक अलमारी में कपड़ों के साथ रुपयों से भरा बैग रखा था, जबकि दूसरी छोटी अलमारी में कपड़ों की तरह नोटों की गड्डियां सजा कर रखी गई थीं। दोनों अलमारियों में गुप्त लॉक के साथ बाहर से भी ताला लगा हुआ था। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे विजिलेंस की दो टीमों जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह को लेकर उनके सरकारी आवास पहुंचीं और तलाशी शुरू की। अलमारी के अलग-अलग खानों में 200 और 500 रुपये के नोटों की गड्डियां रखी मिलीं। पास रखी दूसरी अलमारी खोली गई तो उसमें दो बड़े बैग मिले, जिनमें 500-



500 रुपये के नोटों के बंडल भरे हुए थे। विजिलेंस टीम बरामद नकदी को लेकर थाने पहुंची। बड़ी मात्रा में नकदी होने के कारण नोटों की गिनती के लिए एलडीएम से मशीन मंगाई गई, जिसके बाद मशीनों से रकम की गिनती की गई। इस दौरान हिरासत में लिए गए जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह अधिकारियों के बीच बैठकर चाय पीते नजर आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) मेरठ सेक्टर की ट्रेप टीम उसमें दो बड़े बैग मिले, जिनमें 500-

कार्यालय में कार्रवाई करते हुए जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और संविदा कर्मी सहायक लिपिक सद्धाम को 85 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यालय की तलाशी के दौरान खनन अधिकारी की दरज से 8 लाख नकद बरामद किए गए, जबकि उनके सरकारी आवास से 63 लाख मिले। इस तरह कार्यालय और आवास से कुल 71 लाख नकद बरामद किए गए। विजिलेंस टीम दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर थाने ने गुरुवार को जिला खनन अधिकारी पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई।

भुज-बरौनी के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन होगी सेवा

संवाददाता
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दी है। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी और 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। रेलवे की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस रात 11:55 बजे बरौनी से चलेगी और अगले दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी। भुज-बरौनी ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी-भुज ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। इस ट्रेन के मार्ग में समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सर्वाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा,

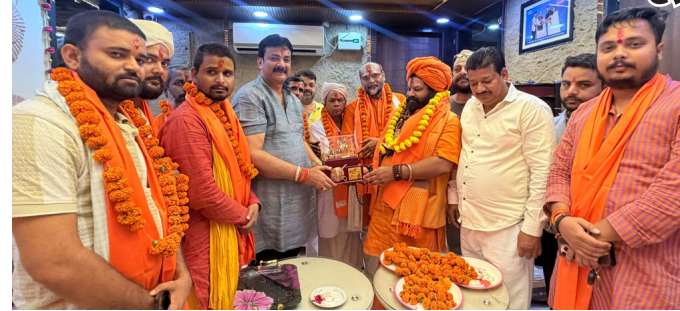


गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होंगे। नई ट्रेन सेवा से देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने ट्रेन संख्या 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस का विस्तार मथुरा स्टेशन तक करने को भी मंजूरी दी है। इससे झांसी, आगरा और मथुरा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध होगी। विस्तार के बाद ट्रेन संख्या 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से मथुरा तक चलेगी, जबकि

ट्रेन संख्या 11902 मथुरा से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए रवाना होगी। मथुरा तक विस्तार के बाद ट्रेन की कुल यात्रा दूरी 217 किलोमीटर से बढ़कर 270 किलोमीटर हो जाएगी। विस्तारित मार्ग पर राजा की मंडी, रुनकता, दीन दयाल धाम और बाद स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होंगे। ट्रेन संख्या 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से शाम 4 बजे रवाना होकर रात 11 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 11902 मथुरा से सुबह 5:05 बजे चलेगी और दोपहर 12:50 बजे तीरंगा लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार, इस विस्तार से झांसी, आगरा और मथुरा के बीच यात्रा कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मार्ग के बीच आने वाले स्टेशनों के यात्रियों को भी बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। श्रीहनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री श्री 1008 महंत राजूदास जी महाराज इन दिनों धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवास पर बुंदेलखंड पहुंचे। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के यहां आयोजित गणेश उत्सव में शामिल होने के बाद महंत राजूदास महाराज जालौन जिले के ग्राम पचोखरा पहुंचे। यहां गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज (राजेश रामायणी जी) के 72वें प्रकटोत्सव पर आयोजित कथा उत्सव एवं भजन संध्या में उन्होंने सहभागिता की। इसके बाद महंत राजूदास महाराज ने भांडेर स्थित रामगढ़ वाली माता के दरबार में विधिवत दर्शन-पूजन किया। उन्होंने खेड़ापति हनुमान जी के चरणों में भी माथा टेककर क्षेत्र की सुख-शांति और जनकल्याण की कामना की। इसके उपरांत



वे दत्तिया स्थित मां पीतांबर के दरबार पहुंचे और विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। झांसी पहुंचने पर महंत राजूदास महाराज ने समाजसेवी डॉ. संदीप सरावगी के कार्यालय का दौरा किया, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान धार्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। महंत राजूदास महाराज ने संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से किए जा

संतों, वीरों और सेवाभावी लोगों की धरती रही है तथा यहां सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाना पुण्य का कार्य है। डॉ. संदीप सरावगी ने महंत राजूदास महाराज का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि संतों का सान्निध्य और आशीर्वाद जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष सेवा समिति का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सहायता और सेवा पहुंचाना है। इसके बाद महंत राजूदास महाराज ने ओरछा में श्री रामराज सरकार के दर्शन-पूजन किए। उन्होंने राष्ट्र एवं समाज के कल्याण और जन-जन में सद्भाव की कामना की। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के बाद महंत राजूदास महाराज गोरखपुर के लिए रवाना हुए, जहां उनका श्री गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन और मुख्यमंत्री से भेंट का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में बेलारूस के राजदूत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

संवाददाता
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के दौरान आयोजित राउंडटेबल चर्चा में भारत में बेलारूस के राजदूत मिखाइल कास्को और बेलारूस

के प्रमुख व्यावसायिक घरानों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। बैठक में उत्तर प्रदेश और बेलारूस के बीच तकनीक आधारित कृषि सहयोग, कृषि मशीनीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, इंजीनियरिंग मिखाइल कास्को और बेलारूस



सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशने के साथ दोनों पक्षों के लिए लाभकारी व्यावसायिक साझेदारी को आगे

बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर बातचीत की।

बांगरमऊ में भारी बिजली कटौती से लोग बेहाल

संवाददाता
उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कस्बा बांगरमऊ और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों रात के समय लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गर्मी और उमस के बीच घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के समय किसी तरह बिजली कटौती सहन कर ली जाती है, लेकिन रात में लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। बिजली नहीं रहने से घरों में पंखे और कूलर बंद हो जाते हैं और उमस के कारण लोगों को सोने तक में परेशानी होती है। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों

के लिए स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। रात की बिजली कटौती का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को बिजली नहीं रहने पर मोबाइल की रोशनी या अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अभिभावकों ने मांग की है कि कम से कम रात के समय बिजली आपूर्ति सुचारु रखी जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि बांगरमऊ विद्युत सब स्टेशन के कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर कई बार स्विच ऑफ मिलता है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाए जाने के कारण उपभोक्ताओं को यह जानकारी भी नहीं मिल पाती कि बिजली कटौती क्यों हुई होती है। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों

उमस और गर्मी में घंटों गुल रहती है बिजली, कंट्रोल रूम का नंबर बंद मिलने और अधिकारियों के फोन न उठाने का आरोप



नगरवासियों ने विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से रात के समय हो रही बिजली कटौती की वास्तविक स्थिति की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर नियमित रूप से चालू रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का फोन पर जवाब देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि बिजली जैसी

मूलभूत सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को रात में घंटों परेशान नहीं होना चाहिए। विभाग को फॉल्ट और जरूरी तकनीकी कार्यों को छोड़कर अनावश्यक कटौती से बचना चाहिए। नगरवासियों ने उच्चाधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर बांगरमऊ में रात की बिजली कटौती की समस्या दूर करने और कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।